



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुकवार, 30 जुलाई, 2004/8 भावण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-9, 22 जुलाई, 2004

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5)/94-10817-822.—जिला पंचायत अधिकारी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने उनके कार्यालय पत्र संख्या-कनर-739/90-152, दिनांक 15-1-2004 अनुसार सूचित किया है कि आप द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर-4, रकबा तादादी 0-07-01, उप मुहाल सारथो, तहसील कल्पा में अतिक्रमण बारे श्री ज्ञान सिंह नेगी से एक शिकायत पत्र दिनांक 29-7-2003 को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच तहसीलदार कल्पा द्वारा करवाई गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि आप द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि के नियमितिकरण का आवेदन दिनांक 14-8-2002 को दिया गया है। परन्तु दिसम्बर, 2000 में ग्राम पंचायत कल्पा के प्रधान पद पर चुनाव हेतु अपने नामांकन पत्र में आपने घोषणा की है कि आप द्वारा किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः आपने उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा करके हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व (ड) के अन्तर्गत स्वयं अयोग्यता अर्जित की है।

अतः आप द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा किये जाने पर हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व (ड) की उल्लंघना की गई है तथा आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) (क) के अन्तर्गत प्रधान पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है। इससे पूर्व कि अन्तिम निष्कासन आदेश पारित किये जायें, इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको छः अगस्त, 2004 से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। यदि आप स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सचिव (पंचायती राज) के समक्ष राज्य सचिवालय, आर्मजडेल स्थित शिमला उनके कार्यालय (कमरा नम्बर 101), दिनांक 6-8-2004 को 3.00 बजे सायं उपस्थित हो सकते हैं।

आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम उपरोक्त के अन्तर्गत आपासी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

शिमला-9, 22 जुलाई, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 13/2004-10803-808.—उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने उनके कार्यालय पत्र संख्या-कनर-2004-170, दिनांक 27-1-2004 के अनुसार सूचित किया है कि आप द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर-75, 78, 276, रकबा तादादी 0-33-40, 254, 255, 256, 257, 271 व 371, रकबा तादादी 0-28-04 डा मुहाल थाच व चोरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर में अतिक्रमण वारे ग्रामीण जागरूक एवं उत्थान समिति ग्राम पंचायत तराण्डा से एक शिकायत पत्र दिनांक 12-8-2003 को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच तहसीलदार निचार से करवाई गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि आप द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि के नियमितिकरण का आवेदन किया गया है। परन्तु दिसम्बर, 2000 में ग्राम पंचायत तराण्डा के प्रधान के पद पर चुनाव हेतु अपने नामांकन पत्र में आपने घोषणा की है कि आप द्वारा किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः आपने उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा करके हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व (ड) के अन्तर्गत स्वयं अयोग्यता अर्जित की है।

अतः आप द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा किये जाने पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व (ड) की उल्लंघना की गई है तथा आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (क) के अन्तर्गत प्रधान पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है। इससे पूर्व कि अन्तिम निष्कासन आदेश पारित किये जायें, इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको छः अगस्त, 2004 से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। यदि आप स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सचिव (पंचायती राज) के समक्ष राज्य सचिवालय आर्मजडेल स्थित शिमला में उनके कार्यालय (कमरा नम्बर 101), दिनांक 6-8-2004 को 3.00 बजे सायं उपस्थित हो सकते हैं।

आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम उपरोक्त के अन्तर्गत आपासी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

शिमला-9, 22 जुलाई, 2004

संख्या पीसीएच-एचए(5)/2001-10797-801.—जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर स्थित रिकांग थिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने उनके कार्यालय पत्र संख्या कनर-739/90-490 दिनांक शून्य के अन्तर्गत सूचित किया है कि आप द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 279/1, रकबा तादादी 0-12-76, उप मुहाल

ठिकरू, तहसील सांगला में अतिक्रमण बारे श्री ज्ञान सिंह नेगी से शिकायत पत्र दिनांक 22-9-2003 को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच तहसीलदार सांगला द्वारा करवाई गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि आप द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि के नियमितिकरण का आवेदन किया गया है। परन्तु दिसम्बर, 2000 में पंचायत समिति कल्पा के सदस्य पद पर चुनाव हेतु अपने नामांकन पत्र में आपने घोषणा की है कि आप द्वारा किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः आपने उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व (ड) के अन्तर्गत स्वयं अयोग्यता अर्जित की है।

अतः आप द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा किए जाने पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) व (ड) की उल्लंघना की गई है तथा आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (क) के अन्तर्गत सदस्य पंचायत समिति के पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है। इससे पूर्व कि अन्तिम निष्कासन आदेश पारित किए जायें, इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको छः अगस्त, 2004 से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। यदि आप स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हों तो सचिव (पंचायती राज) के समक्ष राज्य सचिवालय आर्मजडेल स्थित शिमला उनके कार्यालय (कमरा नम्बर 101), दिनांक 6-8-2004 को 3.00 बजे सायं उपस्थित हो सकते हैं।

आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम उपरोक्त के अन्तर्गत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

शिमला-9, 22 जुलाई, 2004

संख्या पीसीएच-एचए(5) 13/2004-10810-815.—उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने उनके कार्यालय पत्र संख्या 4नर-2004-171, दिनांक 27-1-2004 के अनुसार सूचित किया है कि आप द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 181, 202, रकबा 0-02-84, उप मुहल घोण्डा, तथा खसरा नम्बर 162, रकबा तादादी 0-03-16, मौजा ठिकरम, तहसील निचार, जिला किन्नौर में अतिक्रमण बारे ग्रामीण जागरूक एवं उत्थान समिति, ग्राम पंचायत तराण्डा से एक शिकायत पत्र दिनांक 12-8-2003 को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच तहसीलदार निचार से करवाई गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि आप द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि के नियमितिकरण का आवेदन किया गया है। परन्तु दिसम्बर, 2000 में ग्राम पंचायत तराण्डा के उप-प्रधान के पद पर चुनाव हेतु अपने नामांकन पत्र में आपने घोषणा की है कि आप द्वारा किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः आपने उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व (ड) के अन्तर्गत स्वयं अयोग्यता अर्जित की है।

अतः आप द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा किए जाने पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व (ड) की उल्लंघना की गई है तथा आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (क) के अन्तर्गत उप-प्रधान के पद से निष्कासित किया जाना प्रस्तावित है। इससे पूर्व कि अन्तिम निष्कासन आदेश पारित किए जायें, इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको छः अगस्त, 2004 से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। यदि आप स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हों तो सचिव (पंचायती राज) के समक्ष राज्य सचिवालय आर्मजडेल स्थित शिमला उनके कार्यालय (कमरा नम्बर 101) दिनांक 6-8-2004 को 3.00 बजे सायं उपस्थित हो सकते हैं।

आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम उपरोक्त के अन्तर्गत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

### ORDER

*Shtmla-9, the 22nd July, 2004!*

**No. PCH-HA (5) 124/2002-10879-885.**—Whereas Shri Rajesh Kumar, Pradhan, Gram Panchayat Sokani-Da-Kot, Development Block Kangra, District Kangra, H. P. was placed under suspension by Deputy Commissioner Kangra, H. P. *vide* order No. 2204-10, dated 20-8-2002 for committing serious lapses and irregularities in the execution of construction of a room in Govt. Primary School building Kharota, resulting into collapse of this building and causing the death of four children and injuries to 18 children.

2. And whereas, regular inquiry u/s 146 (1) of the H. P. Panchayati Raj Act, 1994 was ordered *vide* order No. PCH-HA (5) 124/2003 dated 30-1-2003 against Shri Rajesh Kumar, and Additional Deputy Commissioner Kangra was appointed as Inquiry Officer. The Inquiry Officer has submitted his inquiry report to this office on 16-1-2004, which was considered by the Government and a show cause Notice for removal was issued to the above Pradhan *vide* this office order of even No. dated 26-3-2004. The reply to the above notice has been submitted by the delinquent Pradhan, which has also been carefully considered.

3. And whereas, it has been conclusively proved by the inquiry report that Shri Rajesh Kumar, Pradhan used substandard material in the construction of one room of GPS Kharota with the result that the same could not resist the debris so brought by the rain water and entire room collapsed, thereby rendering the entire expenditure incurred on the construction of this school room as infructuous, besides a loss of human life of 4 innocent children and serious injuries to 18 children. This loss is not only serious but is irreparable. The aforesaid Pradhan was solely responsible for the execution of above work under his supervision with technical guidance of the concerned Technical Authority. Thus Shri Rajesh Kumar, Pradhan Gram Panchayat Sokani-Da-Kot has failed to maintain the required degree of integrity, responsibility and accountability besides devotion in the discharge of duties in his capacity of Pradhan.

Hence, for the reasons, recorded heretoforth, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of powers vested in him under section 146 (1) of the H. P. Panchayati Raj Act, 1994 is pleased to remove said Shri Rajesh Kumar, Pradhan, Gram Panchayat Sokni-Da-Kot Development Block Kangra, District Kangra, H. P., forthwith.

These orders shall come into force with immediate effect.

By order,

Sd/-  
Secretary (Panchayats).